



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 16 मार्च, 1989/25 फाल्गुन, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88-पर्यटन (सचि).—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल (जुगेहड़, मौजा बण्डी) तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पटन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है। अतएव: एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी

(नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि पर कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

जिला: कांगड़ा :

तहसील:-कांगड़ा:

महाल	खसरा नं०	क्षेत्रफल हकटेयों टेयर में	1	2	3	4	5
1	2	3					
जुगेहड़, मौजा				96	0	08	09
वण्डी				97	0	07	15
				89/1	0	03	53
				544/199	0	01	98
	464/3/1	0 07 24		545/199/1	0	00	75
	465/3/1	0 20 32		100	0	02	78
	467/3/1	0 03 14		101	0	00	40
	513/489/1	0 03 99		102	0	07	67
	514/489/1	0 09 98		103/1	0	09	75
	4/1	0 82 77		104/1	0	10	23
	4/2	0 01 44		114/1	0	01	92
	519/51	4 96 17		546/115/1	0	01	66
	80	0 07 48		120/1	0	00	49
	81	0 06 51		121/2	0	00	10
	82	0 19 52		122/2	0	02	38
	83	0 06 30		124/2	0	02	13
	84	0 06 08		125	0	19	13
	85	0 04 72		126	0	24	46
	86	0 05 24		127	0	05	95
	87	0 03 71		128	0	02	08
	530/90	0 03 45		128/1	0	02	38
	531/90/1	0 02 41		128/2	0	02	20
	532/91	0 01 20		552/129/1	0	40	95
	533/91/1	0 05 47		552/129/2	0	34	71
	534/92	0 01 60		553/129	0	04	74
	535/92	0 12 61		554/130	0	02	18
	536/92	0 11 40		556/130	0	01	49
	537/93	0 03 06		558/130	0	02	94
	538/93	0 03 08		131	0	02	28
	539/93	0 03 04		132	0	05	92
	540/93	0 03 10		133/1	0	09	23
	541/93	0 03 08		133/2	0	05	44
	542/95	0 12 62		134	0	05	79
	543/95	0 10 19		135	0	02	64
	77	0 06 50		136	0	03	84

1	2	3	1	2	3
137	0 16 19		159	0 20 82	
138	0 03 93		160	0 10 50	
139	0 02 50		161	0 04 96	
140	0 01 08		163	0 01 35	
141	0 26 24		164	0 01 71	
142	0 03 75		165 1	0 03 58	
143	0 01 45		166	0 00 58	
144	0 06 32		167	0 05 18	
145	0 01 58		169 1	0 03 30	
146	0 03 42		170 1	0 02 62	
147	0 05 50		557 17 1	0 04 22	
148	0 03 94		172 1	0 00 48	
149	0 02 04		173 1	0 01 22	
150	0 03 64		175 2	0 04 75	
151	0 06 61		176 1	0 00 22	
152	0 04 99		177 2	0 00 48	
153	0 02 16		178 2	0 06 39	
154	0 06 79		179 2	0 03 08	
155	0 22 54		214 2	0 02 84	
156	0 00 56				
157	0 01 19	कुल कित्ता ..	107	12 19 13	
158	0 07 83				

शिमला-171002, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88—पर्यटन (सचि):—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल रिच्छवालू, मौजा वण्डी, तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पतन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अतिआवश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है। उक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि का अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अतिआवश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व, भूमि पर कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी		1	2	3
जिला: कांगड़ा	तहसील: कांगड़ा	789	0 03	61
		790	0 01	80
महाल	खसरा नं०	791	0 00	27
1	2	792।1	0 01	89
	3	793।1	0 18	83
रिच्छ्याल, मौजा	738।2	950	0 21	02
वण्डी।	743।2	951	0 07	00
	744।1	952	0 07	04
	754।1	953	0 16	32
	748	954	0 00	46
	751।1	955	0 00	23
	760।1	956	0 00	36
	761।1	957	0 00	30
	762	958	0 00	64
	763	960	0 87	08
	764	961	0 00	76
	765	962	0 03	92
	766	963	0 04	68
	767	964।1	0 07	51
	768	965।1	0 14	51
	769	966	0 00	72
	770	967	0 00	38
	771	968।1	0 01	08
	772	970।1	0 00	38
	773	978।1	0 00	70
	774	979।1	0 01	15
	775	980।1	0 00	12
	776	1051।1	0 01	56
	777	1052।1	0 00	50
	778	1053।1	0 01	21
	779	1054।2	1 33	22
	780	1055	0 31	13
	781	1056	0 17	23
	782	1057।1	0 14	43
	783	1060।1	0 03	98
	784	1062।1	0 12	10
	786	1068।1	0 02	59
	787।2			
	788	कुल कित्ता	71	8 48 36

शिमला-2, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88-पर्यटन (सचि०).—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल सनौरा, मौजा दुगियारी, तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पतन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि को अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व, भूमि का कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : कांगड़ा

तहसील : कांगड़ा:

महाल	खसरा नं०	क्षेत्रफल हैक्टेयरों में	1	2	3
1	2	3			
सनौरा	434/1	0 02 92		450	0 00 15
	435	0 00 52		451	0 00 25
	436	0 00 32		452	0 00 60
	437	0 00 62		453	0 01 47
	438/1	0 00 54		822/454	0 02 49
	439/1	0 00 04		823/454	0 02 43
	440	0 00 80		455/1	0 06 99
	441	0 00 15		456/1	0 08 31
	442	0 02 35		457	0 00 55
	443	0 01 01		458	0 00 35
	444	0 01 88		459	0 00 20
	445	0 02 86		460	0 00 51
	446	0 02 41		461	0 00 66
	447	0 00 66		462	0 00 42
	448	0 00 39		463	0 01 40
	449	0 00 28		464	0 00 50
				465	0 00 66
				469/1	0 00 12
				470/1	0 05 57
				471	0 01 26

1	2	3	1	2	3
472	0 00 30		511	0 01 72	
473	0 01 60		512	0 02 66	
474	0 03 39		513	0 00 40	
475/1	0 03 09		514	0 01 26	
485	0 07 25		515	0 00 09	
488/1	0 16 16		516	0 01 98	
489	0 01 94		517	0 02 88	
490	0 21 16		518	0 03 87	
491	0 00 80		519	0 04 34	
492	0 22 78		520	0 02 85	
493	0 01 32		521	0 02 24	
494	0 10 39		522	0 01 64	
824/495	0 07 73		523	0 04 16	
825/494	0 11 41		524	0 03 79	
496	0 00 48		525	0 01 23	
497	0 00 39		526	0 02 28	
498	0 13 33		528	0 00 42	
499	0 14 77		529	0 41 04	
501	0 01 20		533	0 01 08	
502	0 00 35		558/1	0 00 39	
503	0 00 50		559/1	0 00 06	
504	0 00 16		580/1	0 00 58	
505	0 01 02		583/1	0 00 09	
507	0 01 47		586/1	0 04 21	
508	0 02 06		587/1	0 00 42	
509	0 01 90		584/1	0 00 09	
510	0 01 05		कुल कित्ता.. 89	2 86 41	

शिमला-2, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88-पर्यटन(सचि०).—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल भेड़ी, मौजा वगडो, तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पतन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अतिआवश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा के उपबन्धों के अधीन इस से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उर मण्डल, अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि को अर्जन करने के आदेश लेने का प्रश्न द्वारा निर्देश दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अतिआवश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि पर कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

जिला : कांगड़ा

तहसील : कांगड़ा

महाल	खसरा नं०	क्षेत्रफल हैक्टरों में
भेड़ी, मौजा वण्डी	13/1	0 07 11
	54/1	0 00 42
	55/1	0 10 56
	56/1	0 09 03
	57/1	0 04 22
	66/1	0 01 36
कुल कित्ता ... 6		0 32 70

आदेश द्वारा,
ए० एन० विद्यार्थी,
वितायुक्त एवं सचिव।

